राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 869/2024

1. राम लाल पाटीदार पुत्र स्व. धूलजी पाटीदार, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी नवा डोरा, डूंगरपुर, डूंगरपुर (राज.)।

2. श्री. धूली पुत्र लालजी, उम्र लगभग 100 वर्ष, निवासी नवा डोरा, डूंगरपुर, डूंगरपुर (राज.)।

3. श्रीमती. पानू देवी पत्नी स्व. राम लाल पाटीदार, उम्र लगभग 95 वर्ष, निवासी नवा डोरा, डूंगरपुर, डूंगरपुर (राज.)।

4. श्रीमती. प्रेमिला पत्नी श्री. राम लाल पाटीदार, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी नवा डोरा, डूंगरपुर, डूंगरपुर (राज.).

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, (राज.) जयपुर (राज.) के माध्यम से।

2. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (राज.)

3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रांघे, उदयपुर, राज.

4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा, उदयपुर (राज.)

5. निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा (राज.)

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री गजेंद्र सिंह राठौड़

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पी.पी. श्री रतन सिंह राजपुरोहित, एसआई, एंटी भ्रष्टाचार ब्यूरो, डूंगरपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>28/08/2024</u>

1. यहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, जिला जयपुर के पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 99/2006 दिनांक 19.04.2006, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) तथा 13(2) के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए वहां से उत्पन्न सभी अन्य परिणामी कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विद्वान विशेष न्यायाधीश, सत्र न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक मामले) के समक्ष दिनांक 09.12.2014 को दायर आरोप-पत्र संख्या 387/2014 भी शामिल है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, राम लाल पाटीदार ने 24.07.1978 से 19.04.2006 तक विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया। छापेमारी के बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 (उनके माता-पिता तथा पत्नी) के खातों को जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता संख्या 4 (याचिकाकर्ता संख्या 1 की पत्नी) और उसकी पुत्रवधू का स्त्री-धन, जो बैंक लॉकर में रखा हुआ था, भी प्रतिवादियों द्वारा जब्त कर लिया गया। भूमि के दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए।

2.2. संबंधित एफआईआर की जांच के बाद, दिनांक 09.12.2014 को आरोप-पत्र संख्या 387/2014 दाखिल किया गया। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता संख्या

1 और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उसका भाई भी शामिल था, जो सरकारी विभाग में कार्यरत था, की आय को आरोप-पत्र में शामिल किया, जिसमें ज्ञात आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया।

2.3. वर्ष 2014 में आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद से अभियोजन पक्ष द्वारा पिछले 10 वर्षों से मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए तत्काल विविध याचिका प्रस्तुत की गई।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों की परस्पर विरोधी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों का सार यह है कि मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी याचिकाकर्ताओं के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। एक ओर, वे झूठे आरोपों के आधार पर अभियुक्त/अंडरट्रायल होने की बदनामी झेल रहे हैं और दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष सबूतों के अभाव में आगे नहीं बढ़ रहा है और बार-बार स्थगन की मांग कर रहा है।

5. याचिकाकर्ता संख्या 2 (पिता - 100 वर्ष) और याचिकाकर्ता संख्या 3 (माता - 96 वर्ष) और याचिकाकर्ता संख्या 4 (पत्नी - 65 वर्ष), वरिष्ठ नागरिक बताए गए हैं। माता-पिता उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं।

6. याचिकाकर्ता संख्या 1 के माता-पिता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, विद्वान लोक अभियोजक ने हालांकि उनकी नाजुक चिकित्सा स्थिति पर कोई विवाद नहीं किया, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 मुख्य आरोपी है, इसलिए वे किसी भी रियायत के हकदार नहीं हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया।

7. आरोप-पत्र में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से याचिकाकर्ता संख्या 1 और उसके भाई के खिलाफ हैं। माना जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के भाई

पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई थी। वह संबंधित समय में सरकारी सेवा में भी था।

8. केस फाइल को ध्यान से देखने के बाद, मैं इस विचार पर पहुंचा हूं कि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 19.04.2006 को एफआईआर दर्ज होने के बाद मुकदमे को समाप्त करने में 18 साल से अधिक का लंबा और अनुचित विलंब हुआ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई गलती न होने के बावजूद यह देरी निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है। 2014 में आरोप पत्र दाखिल होने के बावजूद किसी भी तरह की प्रगति न होना न्याय प्रशासन के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। इस तरह की देरी कानूनी सिद्धांत को कमजोर करती है कि देरी से मिला न्याय न्याय से वंचित करने के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके विपरीत, जल्दबाजी में किया गया न्याय न्याय को दफनाने के समान है। लेकिन मामला पहले वाली श्रेणी का है, न कि बाद वाली श्रेणी का।

9. अभियोजन पक्ष आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से बिना किसी उचित कारण के कोई सबूत पेश करने या मामले में कोई सार्थक प्रगति करने में विफल रहा है। ठोस सबूत पेश किए बिना बार-बार स्थगन पर अभियोजन पक्ष का भरोसा मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थता को दर्शाता है। यह स्थिति याचिकाकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करती है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करती है क्योंकि वे अप्रमाणित आरोपों के आधार पर ट्रायल के तहत बने हुए हैं।

10. जांच के दौरान, अधिकारियों ने न केवल याचिकाकर्ता नंबर 1 (राम लाल पाटीदार) बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति भी जब्त कर ली, जिसमें उनके स्त्री-धन जैसे निजी सामान भी शामिल हैं। ये कार्रवाइयाँ आय से अधिक संपत्ति की जाँच के लिए ज़रूरी से परे हैं, जिससे पूरे परिवार को अनुचित

परेशानी हो रही है। जाँच में असंबंधित परिवार के सदस्यों को शामिल करने से उनके खिलाफ़ मामले की दमनकारी प्रकृति और बढ़ जाती है।

11. इसके अलावा, याचिकाकर्ता संख्या 2 (पिता) और संख्या 3 (माता) वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी आयु क्रमशः 100 और 96 वर्ष है। उनकी अधिक आयु और खराब स्वास्थ्य के कारण इस लंबी सुनवाई में उनका शामिल होना अत्यधिक अन्यायपूर्ण और अनुचित है। ऐसे अधिक आयु के व्यक्तियों पर मुकदमे का बोझ, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 के खिलाफ आरोपों के केंद्र में नहीं हैं, यदि कुछ और नहीं तो करुणा के आधार पर मामले में उनकी भागीदारी को रद्द करने का मामला बनता है, जो एक उचित आधार प्रतीत होता है, यह देखते हुए कि वे वास्तव में आरोपी नहीं हैं, बल्कि अपने बेटे को केवल नाम के ऋणदाता हैं, यदि हैं।

12. याचिकाकर्ता के भाई, जो उस समय एक सरकारी कर्मचारी भी थे, पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न होने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। अभियोजन पक्ष के आचरण में यह असंगति बताती है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और उनके परिवार के खिलाफ मामला पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। यदि याचिकाकर्ता के भाई जैसे किसी प्रमुख व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, तो इससे परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी मामले की वैधता पर संदेह पैदा होता है।

13. इस तर्क में दम है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप झूठे हैं, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष मामले को आगे बढ़ाने या मुकदमे को निष्कर्ष पर लाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा है। 2014 से प्रगति की कमी इस तर्क को पुष्ट करती है कि आरोप निराधार हो सकते हैं या कम से कम मजबूत सबूतों द्वारा समर्थित नहीं हो सकते हैं, जो आरोपों को खारिज करने का औचित्य साबित करते हैं।

14. याचिकाकर्ताओं के माता-पिता की वृद्धावस्था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मानवीय दृष्टिकोण की मांग करती हैं। अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहे व्यक्तियों को बिना किसी ठोस आरोप के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करना क्रूर और अन्यायपूर्ण दोनों है। कथित अपराध में याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4 (माता-पिता और पत्नी) की प्रत्यक्ष संलिप्तता की कमी को देखते हुए, उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए एक मजबूत आधार बनाया गया है क्योंकि वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सुरंग में एक भी प्रकाश की झिलमिलाहट के बिना लंबे समय तक मुकदमेबाजी की पीड़ा झेल चुके हैं।

15. परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण देरी के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष द्वारा एक मजबूत मामला पेश करने में विफलता, पत्नी और माता-पिता को आरोप पत्र में अनुचित रूप से शामिल करना और याचिकाकर्ता संख्या 2 और संख्या 3 की स्वास्थ्य स्थिति, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के बीमार माता-पिता और पत्नी (याचिकाकर्ता संख्या 2 से 4) के खिलाफ आरोप पत्र खारिज किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

16. याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के साथ इस उम्मीद के साथ किया जाता है कि आगे लंबित मुकदमे की कार्यवाही बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के कहने पर, यथासंभव शीघ्रता से समाप्त की जाएगी।

17. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा हो गया है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।